3 ओवरलोड वाहनों से आवागमन हो रहा बाधित

5 भारतीय राजनीति में एक अलग पहचान स्थापित

6 क्या पानी के लिए जमीन भी हाथ खड़े कर रही है?

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 03 प्रति सोमवार, 25 मई 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

क्या भिंड जिले में कानून से ऊपर हो गए हैं मंत्री राकेश शुक्ला?

शुक्ला ने बनवाया था मोदी की अवमानना करने वाले सज्जन सिंह यादव को भिंड जिला का किसान अध्यक्ष

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश के बीजेपी नेता और मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहतें नहीं मान रहे हैं। भिंड के मेहगाँव के सज्जन सिंह यादव जिसे मंत्री राकेश शुक्ला ने जिला किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनवाया था उन्होंने 700 गाड़ियों का काफिला लेकर रैली निकाली। हालांकि भाजपा ने उनको पद विहीन कर दिया। पर जिस मंत्री की पैरवी से बने वह अध्यक्ष उन्हें शिष्टाचार का पाठ क्यों नहीं पढ़ाया गया। आज राकेश शुक्ला से ज्यादा अकर्मण्य नेता मोहन कैबिनेट में नहीं है, जिन्होंने विभाग का कुल 1% बजट ईस्तेमाल कर पाए, खबर यह है कि सौर ऊर्जा के नाम पर ऊर्जा विकास निगम में हर मेगावाट पर एक लाख रुपये की रिश्वत अनुमती के नाम पर मांगी जाती है। साथ ही चाहे अवैध रेत

खनन हो या उनके पुत्र आलोक का हस्ताक्षेप एवं क्षेत्र में बाहुबल का उपयोग, बेटे के ससुर की क्षेत्र में गुन्डागर्दी से लेकर भ्रष्टाचार तक सब कुछ हो रहा है। आखिर बीजेपी अपने इस नेता पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है। मध्यप्रदेश की राजनीति में समय-समय पर ऐसे प्रसंग सामने आते रहे हैं, जब सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हुए। इन दिनों प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला को लेकर भिंड जिले से जिस प्रकार की चर्चाएं और आरोप सामने आ रहे हैं, उन्होंने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मंत्री का पद केवल सत्ता का प्रतीक नहीं होता, बल्कि वह जवाबदेही, नैतिकता और जनविश्वास का भी दायित्व लेकर चलता है। ऐसे में यदि किसी मंत्री के नाम के साथ अवैध खनन, प्रशासनिक हस्तक्षेप और असामाजिक तत्वों को संरक्षण जैसे आरोप जुड़ने लगें, तो यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं रह जाता, बल्कि शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह बन जाता है। (शेष पेज 2 पर)

क्या छत्तीसगढ़ के बाद पंजाब में भी कांग्रेस की नैय्या डुबायेंगे भूपेश?

बैठक में बवाल के बाद पंजाब कांग्रेस में तेज हुई कलह

-विजया पाठक

पंजाब कांग्रेस इन दिनों जिस राजनीतिक असमंजस और आंतरिक असंतोष के दौर से गुजर रही है, उसके केंद्र में पार्टी के प्रदेश प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी थी, वह अब पार्टी के भीतर ही सवालों के घेरे में दिखाई देने लगी है। हाल के घटनाक्रमों ने यह संकेत दिया है कि पंजाब कांग्रेस में संगठनात्मक समन्वय की कमी और नेतृत्व को लेकर असंतोष तेजी से बढ़ रहा है। पिछले दिनों पंजाब में आयोजित कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक में जिस प्रकार का माहौल देखने को मिला, उसने पार्टी की अंदरूनी स्थिति को सार्वजनिक कर दिया। सू त्रों के अनुसार बैठक के दौरान कई नेताओं ने संगठनात्मक कार्यशैली और संवादहीनता को लेकर नाराजगी जाहिर की। कहा जा रहा है कि स्थानीय नेताओं को यह महसूस होने लगा है कि प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों को समझने के बजाय शीर्ष नेतृत्व केवल औपचारिक बैठकों तक सीमित रह गया है। (शेष पेज 3 पर)

बरगी जैसे हादसे से बचाने के लिए शहर का प्रकाश तरण पुष्कर 6000 मेंबर को सिखा रहा है तैराकी

प्रबंधक हेमंत झारिया और उनकी टीम के अनुशासन और मेहनत के कारण राष्ट्रीय कसौटी पर खरा उतरता है प्रकाश तरण पुष्कर

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में संचालित राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल में शामिल प्रकाश तरुण पुष्कर अपने प्रबंधक हेमंत झारिया के नेतृत्व में हर महीने में करीब 4000 लोग तैराकी सीखकर और उसमें दक्षता हासिल कर भविष्य में बरगी जैसे हादसे रोकने का महत्पूर्ण कार्य कर रहे हैं। राजधानी में चाहे नौकरशाह, राजनीतिज्ञ, पत्रकार के साथ-साथ आम जनता की पहली पसंद प्रकाश तरण पुष्कर है और उसका सबसे बड़ा कारण यहां के प्रबंधक हेमंत झारिया और उनकी टीम है। (शेष पेज 5 पर)

रोजगार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का आधार बन रहा छत्तीसगढ़

पर्यटन विस्तार और निवेश के नए आयाम गढ़ती साय सरकार

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ लंबे समय तक अपनी खनिज संपदा, घने वनों, जनजातीय संस्कृति और प्राकृतिक विविधता के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राज्य ने अपनी पहचान को एक नए आयाम देने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। विशेषकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव सा य के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पर्यटन को केवल सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के प्रदर्शन का माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे विकास, निवेश, रोजगार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार के रूप में स्थापित करने की दिशा में गंभीर पहल की है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ पर्यटन के क्षेत्र में जिस परिवर्तनकारी यात्रा से गुजर रहा है, वह राज्य के विकास मॉडल की नई पहचान बनती दिखाई दे रही है। राज्य सरकार का सबसे महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय पर्यटन को उद्योग का दर्जा देना रहा है। (शेष पेज 2 पर)

भिंड में सत्ता, संरक्षण और विवादों के केंद्र बने राकेश शुक्ला, अपने बेटे को बना रखा है मेहंगाँव का अन ऑफिशीयल मंत्री, बेटे के ससुर का क्षेत्र में है बाहुबल

(पेज 1 का शेष)

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना पर उतरे शुक्ला

भिंड और चंबल क्षेत्र लंबे समय से रेत खनन और उससे जुड़े विवादों के कारण चर्चा में रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर सख्त निर्देश दिए गए, लेकिन इसके बावजूद यदि अवैध खनन के आरोप लगातार सामने आते हैं, तो यह प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि मंत्री राकेश शुक्ला के प्रभाव के कारण प्रशासन कई मामलों में दबाव में कार्य करने को मजबूर दिखाई देता है। यदि इन आरोपों में सच्चाई है, तो यह अत्यंत गंभीर विषय है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन को कानून और संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दबाव के आधार पर।

खुद मुख्यमंत्री सचिवालय लाये थे किसान नेता को

पिछले दिनों भिंड जिले में एक किसान नेता और जिला अध्यक्ष के खिलाफ सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ रैली निकालने का मामला भी चर्चा का विषय बना। आरोप लगाए जा रहे हैं कि संबंधित व्यक्ति मंत्री के करीबी माने जाते हैं और राजनीतिक संरक्षण के कारण प्रशासन उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने से बचता रहा। यह स्थिति सत्ता और संगठन के उस खतरनाक गठजोड़ की ओर संकेत करती है, जिसमें जनप्रतिनिधि अपने प्रभाव का उपयोग कानून व्यवस्था से ऊपर दिखाई देने के लिए करने लगते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक निकटता कभी भी कानून से ऊपर नहीं हो सकती।

प्रशासन पर हावी है शुक्ला का रौब

सबसे अधिक चिंता का विषय प्रशासनिक ढांचे में बढ़ता राजनीतिक हस्तक्षेप माना जा रहा है। भिंड जिले में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में मंत्री की अनुपस्थिति के बाद उनके पुत्र आलोक शुक्ला को मुख्य अतिथि बनाए जाने की चर्चा ने कई सवाल खड़े कर दिए। सरकारी कार्यक्रम किसी परिवार विशेष की निजी जागीर नहीं हो सकते। यदि प्रशासन किसी मंत्री के परिजन को केवल राजनीतिक प्रभाव के कारण मंच पर प्रमुखता देता है, तो यह प्रशासनिक निष्पक्षता की भावना के विपरीत माना जाएगा। इससे यह संदेश जाता है कि जिले का प्रशासनिक ढांचा जनहित के बजाय राजनीतिक प्रभाव के अनुसार संचालित हो रहा है।

आपराधिक गतिविधियों को संरक्षण देने का आरोप

चंबल क्षेत्र पहले ही अपराध और अवैध गतिविधियों की छवि से लंबे समय तक संघर्ष करता रहा है। ऐसे में यदि किसी जनप्रतिनिधि पर असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने के आरोप लगते हैं, तो यह पूरे क्षेत्र की सामाजिक संरचना के लिए चिंता का विषय बन जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई ऐसे तत्व, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वे राजनीतिक संरक्षण के कारण खुले तौर पर सक्रिय हैं। यदि सत्ता का उपयोग कानून व्यवस्था मजबूत करने के बजाय संरक्षणवाद के लिए होने लगे, तो इससे जनता का विश्वास कमजोर होता है।

मध्यप्रदेश की वर्तमान सरकार लगातार सुशासन, पारदर्शिता और विकास की बात करती रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी प्रशासनिक कसावट और जवाबदेही पर जोर देते दिखाई देते हैं। ऐसे में यदि किसी मंत्री को लेकर लगातार विवाद सामने आते हैं, तो सरकार की छवि प्रभावित होना स्वाभाविक है। विपक्ष को भी ऐसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का अवसर मिलता है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार इन आरोपों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि लोकतंत्र में आरोप लगना और उनका सिद्ध होना दो अलग-अलग बातें हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि को दोषी ठहराने से पहले तथ्यों और जांच की प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। लेकिन जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक एक जैसे आरोप और चर्चाएं बनी रहें, तो सरकार और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वे स्थिति स्पष्ट करें। लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास को बनाए रखने का भी दायित्व है। राजनीति का उद्देश्य समाज को दिशा देना और विकास की राह पर आगे बढ़ाना होना चाहिए। यदि मंत्री पद का उपयोग प्रभाव, दबाव और संरक्षण की राजनीति के लिए होने लगे, तो इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता कमजोर होती है। भिंड और चंबल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को आज आवश्यकता है पारदर्शी प्रशासन, कानून के समान पालन और विकास आधारित राजनीति की। जनता भी अब केवल भाषणों से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि जवाबदेही और परिणाम चाहती है।

आखिर कब तक चलेगा शुक्ला का बोलबाला

राकेश शुक्ला को लेकर उठ रहे सवाल आने वाले समय में केवल एक मंत्री की राजनीतिक चुनौती नहीं होंगे, बल्कि यह प्रदेश की शासन व्यवस्था की परीक्षा भी बन सकते हैं। सरकार यदि समय रहते इन मुद्दों पर स्पष्ट और कठोर रुख अपनाती है, तो जनता के बीच भरोसा मजबूत होगा। अन्यथा ऐसे विवाद विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकते हैं। लोकतंत्र में सत्ता की सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास होती है, और वही विश्वास किसी भी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी माना जाता है।

पर्यटन विस्तार और निवेश के नए आयाम गढ़ती साय सरकार

(पेज 1 का शेष)

यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि निवेश, अधोसंरचना और आर्थिक गतिविधियों को गति देने वाला कदम साबित हो रहा है। जब किसी क्षेत्र को उद्योग का दर्जा मिलता है, तब निवेशकों को अनेक नीतिगत सुविधाएं, प्रोत्साहन और संस्थागत समर्थन प्राप्त होता है। इससे निजी निवेश आकर्षित होता है और विकास की संभावनाएं व्यापक रूप से बढ़ती हैं। साय सरकार के इस निर्णय ने पर्यटन क्षेत्र को नई ऊर्जा प्रदान की है और निवेशकों के लिए विश्वास का वातावरण तैयार किया है।

पर्यटन के विकास पर चर्चा

छत्तीसगढ़ में पर्यटन के विकास की चर्चा बस्तर के बिना अधूरी है। कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में चर्चित रहा बस्तर आज अपनी नई पहचान बना रहा है। यह परिवर्तन केवल सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी दिखाई देता है। बस्तर अब संघर्ष की भूमि नहीं, बल्कि संभावनाओं की धरती के रूप में उभर रहा है। घने वन, झरने, पहाड़ियां, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध जनजातीय संस्कृति आज देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। बस्तर की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सांस्कृतिक विशिष्टता है। यहां के जनजातीय समुदायों की जीवनशैली, लोकनृत्य, परंपराएं, हस्तशिल्प और उत्सव पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। राज्य सरकार ने इन सांस्कृतिक तत्वों को पर्यटन से जोड़कर स्थानीय समुदायों को विकास की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया है। इससे पर्यटन केवल बाहरी गतिविधि नहीं रहा, बल्कि स्थानीय समाज की भागीदारी वाला मॉडल बनकर सामने आया है।

स्थायी और प्रभावी मॉडल का निर्माण

साय सरकार की नीतियों की सबसे उल्लेखनीय विशेषता सामुदायिक सहभागिता पर बल देना है। पर्यटन का वास्तविक लाभ तभी संभव है जब स्थानीय लोग उसकी प्रक्रिया का हिस्सा बनें। बस्तर के कई क्षेत्रों में ग्रामीणों ने स्वयं श्रमदान कर पर्यटन स्थलों को विकसित किया है। उयधीर नाले जैसे स्थान इसका उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जहां स्थानीय समुदाय ने अपनी पहल से प्राकृतिक स्थल को आकर्षक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया। यह मॉडल बताता है कि सरकार और समाज जब साथ मिलकर कार्य करते हैं तो विकास अधिक स्थायी और प्रभावी होता है। राज्य सरकार ने पर्यटन के विविध आयामों पर समान रूप से ध्यान दिया है। केवल पारंपरिक पर्यटन तक सीमित रहने के बजाय ईको-टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, जल पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन जैसे क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। वर्तमान दौर का पर्यटक केवल दर्शनीय स्थलों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह स्थानीय संस्कृति, अनुभव और प्रकृति के साथ जुड़ना चाहता है। इसी दृष्टि से छत्तीसगढ़ ने पर्यटन की बहुआयामी संरचना विकसित करने का प्रयास किया है।

रोज़गार और स्व-रोज़गार के अवसर

पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से होम-स्टे जैसी योजनाओं को प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना केवल पर्यटकों को स्थानीय अनुभव उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने का माध्यम भी बनती है। इससे गांवों में स्व-रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं और पर्यटन का लाभ सीधे स्थानीय समाज तक पहुंच रहा है। स्थानीय युवाओं के लिए गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम, हस्तशिल्प प्रोत्साहन योजनाएं और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर भी तैयार किए जा रहे हैं। लंबे समय तक रोजगार के सीमित अवसरों के कारण युवाओं को बड़े शहरों की ओर पलायन करना पड़ता था, लेकिन अब पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था स्थानीय स्तर पर अवसर पैदा कर रही है। यह केवल आर्थिक बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का संकेत भी है।

सकारात्मक छवि का किया निर्माण

किसी भी पर्यटन क्षेत्र के विकास में बुनियादी अधोसंरचना की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। सड़क संपर्क, आवास, पेयजल, स्वच्छता, संचार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक होती हैं। साय सरकार ने इन क्षेत्रों में भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है। बेहतर सड़क नेटवर्क और पर्यटन स्थलों तक आसान पहुंच ने पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यटन क्षेत्र में डिजिटल माध्यमों का उपयोग भी उल्लेखनीय है। आज पर्यटन केवल पारंपरिक प्रचार तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन प्रचार के माध्यम से छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे राज्य की सकारात्मक छवि मजबूत हुई है।

औद्योदिक विकास को मिल रही गति

निवेशकों के दृष्टिकोण से देखें तो पर्यटन उद्योग में संभावनाओं का विस्तार तेजी से हुआ है। होटल, रिसॉर्ट, ईको-कैंप, एडवेंचर गतिविधियां, परिवहन सेवाएं और स्थानीय उत्पादों से जुड़े अनेक क्षेत्रों में निजी निवेश के अवसर तैयार हुए हैं। उद्योग का दर्जा मिलने से निवेशकों को यह भरोसा मिला है कि राज्य सरकार दीर्घकालिक नीति और संस्थागत समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज प्रतिस्पर्धा केवल औद्योगिक विकास की नहीं, बल्कि अनुभव आधारित अर्थव्यवस्था की भी है। पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जो कम लागत में व्यापक रोजगार पैदा करता है और समाज के विभिन्न वर्गों को विकास से जोड़ता है। यही कारण है कि विश्व स्तर पर पर्यटन को आर्थिक वृद्धि का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है।

पर्यटन विकास की नई रणनीति

छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस प्रकार पर्यटन को विकास की रणनीति से जोड़ा है, वह केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। बस्तर जैसे क्षेत्रों में आया परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि सही नीतियां, दूरदर्शी नेतृत्व और स्थानीय सहभागिता मिलकर किसी भी क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती हैं। आज नया छत्तीसगढ़ केवल संसाधनों का राज्य नहीं, बल्कि संभावनाओं का प्रदेश बनकर उभर रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में उठाए गए कदम आने वाले समय में राज्य की अर्थव्यवस्था, निवेश और रोजगार के नए अध्याय लिख सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पर्यटन विकास की यह पहल केवल योजनाओं का विस्तार नहीं, बल्कि एक ऐसे भविष्य की आधारशिला है जहां विकास और संस्कृति साथ-साथ आगे बढ़ते दिखाई देते हैं।

शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याएं हो रही हल: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलौदाबाजार जिले के करहीबाजार में आयोजित समाधान शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य सरकार को गांव-गांव तक पहुंचाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करना और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह जानने के लिए गांवों तक पहुंच रही है कि लोगों को पानी, बिजली, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाएं समय पर मिल रही हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि रायपुर में बैठकर ग्रामीणों की समस्याओं को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, इसलिए पूरी सरकार गांवों में पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक अनेक स्थानों पर शिविर संपन्न हो चुके हैं तथा आगामी दिनों में भी शिविरों का आयोजन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को प्राथमिकता के साथ पूरा किया है। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और दो वर्षों का बकाया बोनस भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं के खातों में 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस योजना से महिलाएं बच्चों की पढ़ाई, घरेलू जरूरतों और छोटे व्यवसायों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं। मुख्यमंत्री साय ने "लखपति दीदी" अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं और आगे करोड़पति दीदी बनने की दिशा में बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार कर रही है। प्रदेश की 6000 से अधिक पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां लोगों को प्रमाण पत्र, राजस्व रिकॉर्ड, बैंकिंग और अन्य सेवाएं गांव में ही उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अब रजिस्ट्री के साथ तत्काल नामांतरण की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे लोगों को अनावश्यक परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कही कि सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू करने जा रही है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याएं ऑनलाइन और टोल फ्री नंबर के जरिए दर्ज करा सकेंगे तथा समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी ने वनाग्नि नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वनाग्नि नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं एवं मानसून तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन संपदाओं को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए रिस्पॉन्स टाइम न्यूनतम रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि वनाग्नि की सूचना मिलने के एक घंटे के भीतर संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचें। मुख्यमंत्री ने वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए शीतल खेत मॉडल को प्रदेश भर में लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने फायर लाइन के आसपास छोटी-छोटी तलैया बनाने, वनाग्नि रोकथाम के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार करने तथा आग बुझाने वाले कार्मिकों को पर्याप्त उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने फॉरेस्ट गार्ड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक हजार नई नियुक्तियां करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम समितियों एवं वन पंचायतों को वनाग्नि रोकथाम के लिए नियमानुसार आवश्यक बजट उपलब्ध कराने को कहा। मुख्यमंत्री ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को देखते हुए वन विभाग के प्रत्येक डिवीजन में पशु चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मोबाइल अलर्ट प्रणाली के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में वनाग्नि की सूचना तत्काल उपलब्ध कराने पर बल दिया।

पेयजल और विद्युत व्यवस्था सुचारू रखने पर जोर: ग्रीष्मकाल को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल टैंकरों की पूरी उपलब्धता बनी रहे तथा क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों को शीघ्र सुचारू किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को पेयजल के लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने मैदानी क्षेत्रों के साथ-साथ तीर्थाटन एवं पर्यटन स्थलों पर भी पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति निर्बाध बनी रहे और ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए और अधिक प्रभावी प्रयास किए जाएं।

मानसून तैयारियों की समीक्षा, प्रभारी सचिव करेंगे स्थलीय निरीक्षण: मुख्यमंत्री ने मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपदों के प्रभारी सचिव अपने-अपने जिलों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लें तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए।

ओवरलोड वाहनों से आवागमन हो रहा बाधित

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। नगर सीमा के अंदर एक और जहां ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चलने से आवागमन अवरुद्ध हो जाता है वहीं बालू, रेत से भरी ओवरलोड ट्रालियां खरीदी केंद्रों में किसानों की भरी ट्रालियों के कारण आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। खरीदी केंद्रों पर प्रभावी किसानों एवं सांठगांठ से निम्न स्तर की उपज खरीदी की जाना चौक चौराहा पर जन चर्चा का केंद्र है। बताया जाता है रहटगांव जिला सहकारी बैंक की अनेक समितियां वन ग्रामों में हैं। खरीदी केंद्रों में प्रभावी किसानों के दबाव अथवा साठगांठ से निम्न स्तर की खरीदी की जाना जन चर्चा का केंद्र बना हुआ है। परंतु इस ओर किसी भी जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। अगर इस ओर ध्यान दिया जाए तो करोड़ों-अरबों का घोटाला उजागर हो सकता है। इसी प्रकार अगर ओवरलोड बालू रेत से भरी चल रही ट्रालियों की रायल्टी चेक की जाए तो प्रतिदिन हजारों रुपए का रायल्टी का शासकीय घोटाला सामने आ सकता है।

हर गांव में बनेगा 'सेहत सुरक्षा कवच', कलेक्टर रजनी सिंह के निर्देश

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। कलेक्टर रजनी सिंह की अध्यक्षता में जनपद पंचायत चांवरपाठा में विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत गजेन्द्र सिंह नागेश, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास राधेश्याम वर्मा, जिला क्षय अधिकारी डॉ. देवेन्द्र रिपुदमन सिंह सहित दोनों विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एवं मैदानी अमला मौजूद रहा। बैठक में विकासखंड चांवरपाठा अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम और सीएचओ के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर रजनी सिंह ने निर्देश दिए कि सभी गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीयन एवं समय पर टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनका समुचित प्रबंधन किया जाए तथा कुपोषित बच्चों की पहचान कर आवश्यक उपचार और निगरानी की जाए। उन्होंने जिले में मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा एचबीएनसी कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी ग्रामों में पात्र व्यक्तियों के शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे। आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।

क्या छत्तीसगढ़ के बाद पंजाब में भी कांग्रेस की नैय्या डुबायेंगे भूपेश?

(पेज 1 का शेष)

क्या जांच एजेंसियों के डर और बीजेपी को खुश करने के लिए कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं बघेल?

यहां सवाल उठता है कि क्या भूपेश बघेल बीजेपी के प्लान के मुताबिक काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के बाद अब पंजाब से भी कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। इसके पीछे बघेल के अपने निजी स्वार्थ हैं। वर्तमान में भूपेश बघेल ईडी, आयकर विभाग और अन्य जांच एजेंसियों के दायरे में हैं और कई केस चल रहे हैं। इन केसों से बचने के लिए वह बीजेपी को खुश करना चाहते हैं। अगले साल पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी वहां अपने पैर जमाना चाहती है। इसके लिए भूपेश बघेल परदे के पीछे से विभीषण की भूमिका में बीजेपी को मदद कर रहे हैं। पंजाब का हालिया मामला इसी से संबंधित है।

स्थानीय नेताओं को पहचाने से किया इनकार

सबसे अधिक चर्चा उस घटना की हुई, जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और दो बार विधायक रहे अवतार सिंह हेनरी को लेकर कथित रूप से ऐसी स्थिति बनी कि प्रभारी नेतृत्व उन्हें पहचानने तक की स्थिति में नजर नहीं आया। पंजाब जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में, जहां क्षेत्रीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व और सामाजिक संतुलन बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वहां इस प्रकार की घटनाएं कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर डालती हैं। कांग्रेस के कई स्थानीय नेताओं का मानना है कि यदि प्रभारी को प्रदेश के विधायकों, वरिष्ठ नेताओं और जमीनी समीकरणों की समुचित जानकारी नहीं होगी, तो संगठन को मजबूत करना कठिन हो जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि पंजाब कांग्रेस को इस समय एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो राज्य की जटिल परिस्थितियों को समझते हुए सभी गुटों को साथ लेकर चले। लेकिन वर्तमान स्थिति में पार्टी के भीतर संवाद और विश्वास का संकट दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि बैठकों में असंतोष खुलकर सामने आने लगा है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर लगातार जारी

भूपेश बघेल के राजनीतिक अतीत को लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय रहने के दौरान उन पर कई प्रकार के आरोप लगे और उनकी ही पार्टी के लोगों ने समय-समय पर उनकी कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न लगाए। अब पंजाब में भी विरोधी गुट इसी पृष्ठभूमि को मुद्दा बनाकर उनकी भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। कुछ राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि कांग्रेस के आंतरिक दस्तावेजों और रणनीतियों को लेकर गोपनीयता का संकट पैदा हो रहा है। पार्टी के भीतर बढ़ती अविश्वास की भावना इन चर्चाओं को और हवा दे रही है। पंजाब कांग्रेस के कई नेता मानते हैं कि यदि समय रहते संगठनात्मक सुधार नहीं किए गए, तो आगामी चुनावों में पार्टी को गंभीर राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

भूपेश की भूमिका पर पुनः विचार करे आलाकमान

दरअसल, पंजाब कांग्रेस पहले ही कई चुनौतियों से जूझ रही है। राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार, शिरोमणि अकाली दल की सक्रियता और भाजपा की नई रणनीतियों के बीच कांग्रेस को मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी थी। लेकिन आंतरिक खींचतान और नेतृत्व को लेकर बढ़ती असहमति ने पार्टी की स्थिति को कमजोर किया है। ऐसे समय में प्रभारी नेतृत्व से अपेक्षा थी कि वह संगठन को एकजुट करने का कार्य करेगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां इसके उलट दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस आलाकमान के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह पंजाब में संगठनात्मक संतुलन कैसे स्थापित करे। यदि स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी लगातार बढ़ती रही, तो इसका सीधा प्रभाव पार्टी के जनाधार पर पड़ सकता है। राजनीतिक दलों में नेतृत्व केवल पद से नहीं, बल्कि संवाद, समन्वय और विश्वास से स्थापित होता है। पंजाब कांग्रेस में यही तत्व फिलहाल कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जिस व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले प्रदेश से पार्टी को समाप्त कर दिया। ऐसे व्यक्ति को पंजाब का प्रभारी बनाकर भेजना कांग्रेस आलाकमान की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। इतिहास में दर्ज है कि जहां-जहां भूपेश बघेल को प्रभारी बनाकर भेजा वहां कांग्रेस की नैया डूबी ही है। इससे लगता है कि बघेल कहीं न कहीं बीजेपी को भी लाभ पहुंचाना चाहते हैं। अभी भी समय है कि आलाकमान भूपेश की भूमिका पर पुनः विचार करे।

सम्पादकीय

प्रधानमंत्री की पांच देशों की यात्रा: कूटनीति के नए क्षितिज और भारत की वैश्विक भूमिका

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हालिया पांच देशों की विदेश यात्रा केवल राजनयिक कार्यक्रमों की श्रृंखला भर नहीं है, बल्कि यह तेजी से बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका, उसकी रणनीतिक प्राथमिकताओं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी सक्रिय उपस्थिति का महत्वपूर्ण संकेत भी है। आज विश्व जिस दौर से गुजर रहा है, वहां भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता, ऊर्जा संकट, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां नई वैश्विक परिस्थितियां निर्मित कर रही हैं। ऐसे समय में भारत की विदेश नीति केवल संबंधों को बनाए रखने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वह वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है।

पिछले एक दशक में भारत की विदेश नीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। पहले जहां विदेश यात्राओं को औपचारिक और सीमित दृष्टिकोण से देखा जाता था, वहीं अब उन्हें आर्थिक विकास, रणनीतिक साझेदारी, वैश्विक प्रभाव और सांस्कृतिक कूटनीति के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने 'पड़ोसी पहले', 'एक्ट ईस्ट', 'ग्लोबल साउथ' और 'वसुधैव कुटुंबकम' जैसे सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देकर दुनिया के साथ अपने संबंधों को नई ऊर्जा दी है। पांच देशों की यह यात्रा भी उसी व्यापक रणनीति का हिस्सा प्रतीत होती है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अब केवल सैन्य शक्ति ही निर्णायक नहीं रह गई है। आर्थिक संबंध, तकनीकी सहयोग, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा सुरक्षा और मानवीय साझेदारी भी उतने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। ऐसे में भारत उन देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहता है जो भविष्य की वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में भूमिका निभा सकते हैं।

भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। दुनिया की बड़ी कंपनियां और निवेशक भारत को अवसरों के विशाल केंद्र के रूप में देख रहे हैं। ऐसे समय में विदेश यात्राएं केवल राजनीतिक संवाद तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि वे निवेश, व्यापार, तकनीक और रोजगार के नए द्वार भी खोलती हैं। विभिन्न देशों के साथ हुए समझौते और सहयोग भविष्य में आर्थिक लाभ का आधार बनते हैं। हालांकि विदेश यात्राओं का मूल्यांकन केवल समझौतों और घोषणाओं के आधार पर नहीं होना चाहिए। उनका वास्तविक प्रभाव दीर्घकालिक संबंधों में दिखाई देता है। यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि इन यात्राओं से भारत को वैश्विक मंचों पर कितना समर्थन मिलता है, संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों में उसकी स्थिति कितनी मजबूत होती है और वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में उसकी भागीदारी किस प्रकार बढ़ती है।

आज दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां कोई एक शक्ति केंद्र निर्णायक नहीं है। ऐसे समय में भारत संतुलित विदेश नीति अपनाते हुए अमेरिका, रूस, यूरोप, पश्चिम एशिया और एशियाई देशों के साथ समान रूप से संबंध बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। यह संतुलन भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत बनकर उभरा है। भारत ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि उसकी विदेश नीति किसी गुट विशेष की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू भारतीय प्रवासी समुदाय भी है। दुनिया के विभिन्न देशों में बसे भारतीय आज केवल सांस्कृतिक पहचान नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव के भी महत्वपूर्ण केंद्र बन चुके हैं। प्रधानमंत्री की यात्राओं में प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद भारत की 'सॉफ्ट पावर' को मजबूत करने का माध्यम भी बनता है। फिर भी विदेश नीति केवल लोकप्रियता या प्रतीकात्मकता का विषय नहीं हो सकती। उसके परिणामों को जमीनी स्तर पर परखा जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वैश्विक मंचों पर बढ़ती प्रतिष्ठा का लाभ देश के नागरिकों, युवाओं, उद्योगों और विकास योजनाओं तक पहुंचे। प्रधानमंत्री की पांच देशों की यात्रा को इसी व्यापक संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। यह यात्रा केवल देशों के बीच संबंधों का विस्तार नहीं, बल्कि उस नए भारत की तस्वीर भी प्रस्तुत करती है जो विश्व मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ-साथ वैश्विक विमर्श को प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि ये यात्राएं केवल कूटनीतिक उपलब्धियां बनकर रह जाती हैं या भारत के भविष्य के विकास और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में ठोस आधार तैयार करती हैं।

सियासी गहमागहमी

कमलनाथ के अनुभवों का लाभ लेने के प्रयास में कांग्रेस

यदि कांग्रेस नेतृत्व वास्तव में कमलनाथ को राज्यसभा के माध्यम से संसद में भेजने पर विचार कर रहा है और इस दिशा में राहुल गांधी की सहमति बन चुकी है, तो इसे केवल एक राजनीतिक नियुक्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे संगठनात्मक संतुलन, अनुभव और राष्ट्रीय राजनीति में वरिष्ठ नेतृत्व की भूमिका जैसे कई आयाम जुड़े हो सकते हैं। कमलनाथ कांग्रेस के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनके पास संगठन, संसदीय राजनीति और प्रशासन का लंबा अनुभव है। मध्यप्रदेश की राजनीति में उनका प्रभाव आज भी बना हुआ माना जाता है। ऐसे में उन्हें राज्यसभा के जरिए संसद में लाना कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसके माध्यम से पार्टी अनुभवी नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक सक्रिय भूमिका देना चाहती हो। राजनीतिक दृष्टि से यह कदम मध्यप्रदेश की आंतरिक राजनीति पर भी असर डाल सकता है। इससे एक ओर संगठन को अनुभव का लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर राज्य में नई पीढ़ी के नेतृत्व के लिए भी अवसरों का विस्तार हो सकता है। हालांकि, इस तरह के निर्णयों का वास्तविक प्रभाव समय और राजनीतिक परिस्थितियां ही तय करती हैं। फिलहाल यह संकेत कांग्रेस के भविष्य के राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा को जरूर गति देता है।

मप्र में मुख्यमंत्री बदले जाने की सरगर्मियां तेज

डॉ. मोहन यादव को लेकर मध्यप्रदेश की राजनीति में समय-समय पर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं या सुगबुगाहट सामने आती रहती हैं, लेकिन भारतीय राजनीति, विशेषकर दलगत संरचनाओं में ऐसी अटकलें अक्सर राजनीतिक विमर्श का हिस्सा होती हैं। केवल चर्चाओं के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। मुख्यमंत्री पद केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि संगठन, राजनीतिक समीकरण और नेतृत्व की रणनीति का संयुक्त निर्णय होता है। डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं, निवेश, सांस्कृतिक और प्रशासनिक पहलों को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं पर चर्चा स्वाभाविक रूप से राजनीतिक हलकों में रुचि पैदा करती है, लेकिन किसी भी बदलाव का आधार केवल अटकलें नहीं बल्कि पार्टी नेतृत्व की आधिकारिक रणनीति होती है। मध्यप्रदेश की राजनीति में यह भी देखा गया है कि सत्ता और संगठन को लेकर समय-समय पर कई तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों को राजनीतिक विश्लेषण की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, न कि अंतिम सत्य के रूप में। राजनीति में संकेतों की अपनी भाषा होती है, लेकिन निर्णय हमेशा तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सामने आते हैं।

हफ्ते का कार्टून

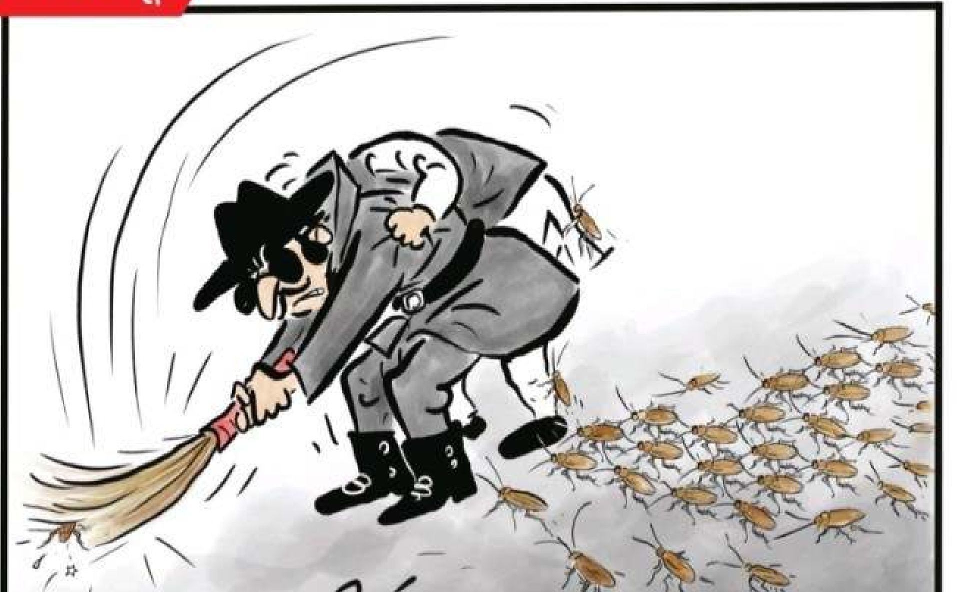

ट्वीट-ट्वीट

आर्थिक तूफ़ान सर पर है, और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफ़ी बाँट रहे हैं!
किसान, युवा, महिलाएँ, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं - PM हंसकर रील बना रहे हैं, और BJP वाले ताली बजा रहे हैं।
यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

रायसेन में जल संकट के कारण कुएँ पर पानी भरने गई 3 आदिवासी छात्राओं की मृत्यु और सीधी में घर में आग लगने से 3 बच्चों की मृत्यु की घटनाएँ हृदय विदारक है।

जल संकट के कारण छात्राओं की मृत्यु की घटना प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और पेय जल व्यवस्था की जमीनी सच्चाई उजागर करती है।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

मनीष तिवारी ने अपनी कार्यशैली और सार्वजनिक जीवन से भारतीय राजनीति में एक अलग पहचान स्थापित की

समता पाठक/जगत प्रवाह

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी भारतीय राजनीति के उन प्रमुख चेहरों में शामिल हैं, जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वे एक कुशल राजनेता, अधिवक्ता, लेखक और प्रभावशाली वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। लंबे समय से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े मनीष तिवारी ने संगठन और संसदीय राजनीति दोनों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। वे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का दायित्व संभाल चुके हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय और बौद्धिक दृष्टिकोण के लिए चर्चा में रहते हैं। मनीष तिवारी का जन्म 08 दिसंबर 1965 को चंडीगढ़ में हुआ। उनका परिवार शिक्षा, सामाजिक चेतना और सार्वजनिक जीवन से जुड़ा रहा है। उनके पिता वी.एन. तिवारी पंजाबी भाषा के विद्वान, लेखक और पंजाब विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे, जबकि उनकी माता अमृत तिवारी एक प्रसिद्ध दंत चिकित्सक और शिक्षाविद थीं। उनके परिवार की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि ने प्रारंभ से ही उनके व्यक्तित्व और विचारों को प्रभावित किया। वर्ष 1984 में उनके पिता की आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला।

उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा चंडीगढ़ के सेंट जॉन्स स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और आगे चलकर दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि (एलएलबी) की डिग्री हासिल की। छात्र जीवन से ही वे नेतृत्व क्षमता और सामाजिक मुद्दों के प्रति सजगता के लिए पहचाने जाने लगे थे। वे विश्वविद्यालय की गतिविधियों और छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। मनीष तिवारी ने बहुत कम उम्र में कांग्रेस की छात्र इकाई से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वे नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और बाद में इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक पहुंचे। संगठन में उनकी सक्रियता, रणनीतिक सोच और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें कांग्रेस के प्रमुख युवा नेताओं में स्थापित किया। कांग्रेस में लगातार सक्रिय भूमिका निभाने के बाद उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। वे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने और अपनी सशक्त तर्कशक्ति तथा राजनीतिक विश्लेषण के कारण मीडिया और संसद में प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई। वर्ष 2009 में उन्होंने पंजाब के लुधियाना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने सांसद के रूप में कई जनहित विषयों को प्रभावी ढंग से उठाया। वर्ष 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया। केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने मीडिया, प्रसारण और संचार से जुड़े अनेक विषयों पर काम किया। इस दौरान वे केंद्र सरकार और यूपीए सरकार के प्रमुख प्रवक्ताओं में भी शामिल रहे। मनीष तिवारी केवल राजनेता ही नहीं, बल्कि एक गंभीर लेखक और विचारक भी हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और समकालीन राजनीति पर कई पुस्तकें लिखी हैं। उनके लेख और विचार राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रकाशित होते रहे हैं। उन्होंने वैश्विक मंचों पर भारत की विदेश नीति और रणनीतिक मुद्दों पर भी अपने विचार रखे हैं।

राजनीतिक जीवन में मनीष तिवारी अपनी स्पष्टवादिता के लिए भी जाने जाते हैं। कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक सुधार और नेतृत्व संबंधी मुद्दों पर उन्होंने समय-समय पर खुलकर अपनी राय व्यक्त की। वे पार्टी के भीतर सुधार की मांग करने वाले नेताओं के समूह में भी शामिल रहे। वर्तमान में मनीष तिवारी राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं और लोकसभा में चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वर्ष 2024 के आम चुनाव में उन्होंने चंडीगढ़ सीट से जीत हासिल की और संसद में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। मनीष तिवारी का जीवन संघर्ष, बौद्धिकता, राजनीतिक प्रतिबद्धता और जनसेवा का उदाहरण है। छात्र राजनीति से शुरू हुई उनकी यात्रा आज राष्ट्रीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में देखी जाती है। उन्होंने अपने विचारों, कार्यशैली और सार्वजनिक जीवन के माध्यम से भारतीय राजनीति में एक अलग पहचान स्थापित की है।

बरगी जैसे हादसे से बचाने के लिए शहर का प्रकाश तरण पुष्कर 6000 मेंबर को सिखा रहा है तैराकी

(पेज 1 का शेष)

प्रकाश तरण पुष्कर एक पब्लिक स्विमिंग पूल है पर खिलाडियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का भोपाल में एकमात्र तरण ताल है। यही कारण है कि प्रबंधक द्वारा खिलाडियों के साथ उनके कोच की विशेष व्यवस्था करवाई जाती है। इसी कारण से पिछले वर्ष इसी पूल से दो खिलाडियों ने राष्ट्रीय पदक हासिल किया।

प्रकाश तरण पुष्कर, भोपाल : शहर की तैराकी पहचान

भोपाल को "झीलों की नगरी" कहा जाता है और इसी पहचान को मजबूत करता है प्रकाश तरण पुष्कर। यह केवल एक स्विमिंग पूल नहीं, बल्कि भोपाल के खेल और फिटनेस संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है। वर्षों से यहाँ हजारों बच्चों, युवाओं और खिलाड़ियों ने तैराकी सीखी है और कई प्रतियोगिताओं में शहर का नाम रोशन किया है। प्रकाश तरण पुष्कर अपनी विशाल एवं सुव्यवस्थित सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शुरुआती तैराकों, बच्चों और प्रोफेशनल खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग पूल उपलब्ध हैं। प्रशिक्षित कोचों द्वारा नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे यह स्थान नए तैराकों के लिए बेहद उपयोगी माना जाता है।

इस स्विमिंग कॉम्प्लेक्स की सबसे बड़ी विशेषता इसका खेल वातावरण है। गर्मियों के मौसम में यहाँ बड़ी संख्या में लोग तैराकी सीखने आते हैं। यह जगह केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि जिला और राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी यहाँ किया जाता है। हाल ही में भोपाल जिला तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन भी यहीं किया गया, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया। आज प्रकाश तरण पुष्कर भोपालवासियों के लिए केवल एक स्विमिंग पूल नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, खेल और अनुशासन का प्रतीक बन चुका है। यह स्थान युवाओं को फिटनेस की ओर प्रेरित करता है और शहर की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठंड में विशेषकर खिलाडियों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधक हेमंत झारिया ने ऑल वेदर स्विमिंग पूल की सुविधा करवाई जिस कारण शहर के खिलाडियों ने ठंड में भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। आपदा की स्थिति होने पर भी यहां त्वरित कार्यवाही की जाती है।

अवैध शराब की बिक्री बंद करने को लेकर कलेक्टर को दिया आवेदन

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह, नर्मदापुरम। जिले के ग्रामीण अंचलों में भी शराब माफियाओं द्वारा अवैध शराब कारोबार सक्रिय रूप से किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। अब शराब की अवैध बिक्री पर पाबंदी लगाने को लेकर डोलरिया तहसील के ग्रामीण जनों ने कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचकर आवेदन देकर गुहार लगाई। कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला आबकारी अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जनसुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि हम सभी ग्रामवासी तहसील डोलरिया के आपसे अनुरोध करते है कि हमारे ग्राम डोलरिया व आसपास गाँव में अवैध रूप से शराब के ठेकेदार द्वारा गाँव गाँव दबाव बनाकर कारोबार संचालित किया जा रहा है। छोटे छोटे गाँवो में दुकान से हटकर अवैध शराब का कारोबार चल रहा है जिससे गाँवो में छोटे छोटे बच्चे,बुर्जुग, महिलाएँ काफी परेशान है। स्कूली बच्चे आने जाने वाली छात्राए काफी परेशान है। अवैध शराब की बिक्री से गाँव के बच्चे और नौजवान ,मजदूर वर्ग के परिवार शराबखोरी का शिकार हो रहे है। जिससे आये दिन नशे में दुघटनाएँ हो रही है। शराब ठेकेदार के आदमियों द्वारा गांवों में चार पहिया वाहनों के द्वारा अवैध रूप से शराब पटकी जा रही है। जिससे नौजवानों, छोटे किसान, मजदूरों को आदी बनाकर उधारी देकर कर्ज में लाद कर अवैध शराब कारोबार में लगाया जा रहा है। जिससे लड़ाई, झगड़े और परिवार बर्बाद हो रहे हैं।

सुवेंदु अधिकारी ने पाँच जिलों- दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार की पहली प्रशासनिक समीक्षा बैठक की

-अमित राय

जगत प्रवाह. सिलीगुड़ी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने उत्तरी बंगाल के पाँच जिलों- दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार की पहली प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रथिन्द्र नाथ बोस, कैबिनेट मंत्री, सांसद राजू बिस्टा, विधायक, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ क्षेत्रीय और जिला पुलिस अधिकारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री अधिकारि ने इस क्षेत्र में कानून का राज बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि नागरिकों के लिए "भय-मुक्त" वातावरण तैयार किया जा सके। उन्होंने सलाह दी कि नागरिक प्रशासन, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच उचित तालमेल सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि प्रशासन लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी बन सके। अगले महीने से सरकार 'अन्नपूर्णा योजना' शुरू कर रही है, जिसके तहत सभी महिलाओं को प्रति माह 3000 रुपये और मुफ़्त बस यात्रा की गारंटी दी जाएगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से लाई गई इस सकारात्मक खबर का उपस्थित सभी लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के क्षेत्र में बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में काम करें। जन कल्याण से जुड़ी सभी योजनाएँ और परियोजनाएँ- जिनमें 'जी-राम-जी' योजना के तहत 125 दिनों के गारंटीशुदा ग्रामीण रोजगार की योजना भी शामिल है- आने वाले दिनों में शुरू की जाएँगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने विभिन्न केंद्र-पोषित परियोजनाओं के लिए जारी किए गए सभी 'अनापत्ति प्रमाण पत्रों' (एनओसी) की पूर्ण समीक्षा करने को कहा है; इन परियोजनाओं को तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा रोक दिया गया था। इस वजह से जन कल्याण की कई परियोजनाएँ रुकी पड़ी हैं और उनमें देरी हुई है। चाय उद्योग की वर्तमान स्थिति और दशा की विस्तृत समीक्षा की जाएगी, जिसमें विभिन्न चाय बागानों के स्वामित्व का मुद्दा, और "चाय श्रमिक योजना" तथा ऐसी ही अन्य योजनाओं में कथित घोटालों के आरोप शामिल होंगे। चाय बागान श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना और चाय उद्योग को पुनर्जीवित करना भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक होगा।

कम खर्च में एक साथ चुनाव

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

एक साथ चुनाव कराने को लेकर संयुक्त संसदीय समिति के निष्कर्ष में सोने में सुहागा कहावत चरितार्थ होने का तथ्य निकलकर आया है। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने दावा किया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से सात लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इस उपाय से देश की जीडीपी में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस बचे धन का उपयोग बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, गरीब कल्याण योजनाएं और अन्य सेवाओं में किया जा सकेगा। याद रहे 41 सदस्यीय यह समिति एक साथ चुनाव से तमाम पहलुओं के साथ दो प्रस्तावित 129वां संविधान संशोधन और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयकों के प्रारूप पर काम कर रही है। चौधरी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इन चुनाव सुधारों से देश को लाभ होना चाहिए। एक साथ चुनाव की दिशा तय करने के लिए सरकार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने मार्च 2024 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार करते हुए चुनाव से संबंधित संशोधन विधेयक को मंजूरी भी दे दी दे थी। इसके प्रारूप को तैयार करने की जिम्मेदारी संसदीय समिति कर रही है। 2029 में एक देश, एक चुनाव, यानी देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ निकाय व पंचायत चुनाव भी एक साथ कराने की दिशा में केंद्र सरकार एक-एक कदम आगे बढ़ रही है। गृहमंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि 2029 के पहले एक साथ चुनाव का प्रबंध कर दिया जाएगा। साफ है, सरकार अपने इस महत्वाकांक्षी वादे को क्रियान्वित करने के प्रति संकल्पबद्ध है। एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो इस समय तक जिन राज्य सरकारों का कार्यकाल बचा होगा, वह लोकसभा चुनाव तक ही पूरा मान लिया जाएगा। वैसे भी आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते रहे हैं, लेकिन 1968 और 1969 में समय के पहले ही कुछ राज्य सरकारें भंग कर दिए जाने से यह परंपरा टूट गई। अब इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में करीब 18 संशोधन करने होंगे। इनमें से कुछ बदलावों के लिए राज्यों की भी अनुमति जरुरी होगी। यदि स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव भी साथ-साथ होते हैं तो फिर मतदाता सूची तैयार निर्वाचन आयोग कराएगा। इस हेतु अनुच्छेद 325 में परिवर्तन करना होगा। साथ ही अनुच्छेद 324-ए में संशोधन करते हुए निगमों और पंचायतों के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ करा लिए जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 368-ए के तहत इस संशोधन विधेयक को आधे राज्यों से भी पास करना जरूरी होगा। इसी अनुरूप केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी अलग से संविधान संशोभन की आवश्यकता पड़ रही है। हालांकि 2029 तक इस कानून का लागू होना फ़िलहाल असंभव लग रहा है।

चूंकि संविधान के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग इकाइयां हैं। इस परिप्रेक्ष्य में संविधान में समानांतर किंतु भिन्न-भिन्न अनुच्छेद हैं। इनमें स्पष्ट उल्लेख है कि इनके चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष के भीतर होने चाहिए। लोकसभा या विधानसभा जिस दिन से गठित होती है, उसी दिन से पांच साल के कार्यकाल की गिनती शुरू हो जाती है। इस लिहाज से संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि एक साथ चुनाव के लिए कम से कम 18 अनुच्छेदों में संशोधन किया जाना जरूरी होगा। विधि आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग और संविधान समीक्षा आयोग तक इस मुद्दे के पक्ष में अपनी राय दे चुके हैं। ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। यदि विपक्षी दल सहमत हो जाते हैं तो दो तिहाई बहुमत से होने वाले ये संशोधन कठिन कार्य नहीं है। क्योंकि राजग के सहयोगी दल जदयू और तेलुगु देशम एक साथ चुनाव के पक्ष में हैं। बीजू जनता दल भी राजग के साथ खड़ा दिखाई दे सकता है। यदि संसद के अन्य विपक्षी दल, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देशहित में निर्णय लें तो यह विधेयक आसानी से दोनों सदनों से पारित हो जाएगा।

अनेक असमानताओं, विसंगतियों और विरोधाभासों के बावजूद भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र से बंधा है। निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्र को एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था देती है, जिससे भिन्न स्वभाव वाली राजनीतिक शक्तियों को केंद्रीय व प्रांतीय सत्ताओं में भागीदारी का अवसर मिलता है। नतीजतन लोकतांत्रिक प्रक्रिया गतिशील रहती है, जो देश की अखंडता व संप्रभुता के प्रति जवाबदेह है। देश में मानव संसाधन सबसे बड़ी पूंजी है। गोया, यदि बार-बार चुनाव की स्थितियां बनती हैं तो मनुष्य का ध्यान बंटता है और समय व पूंजी का क्षरण होता है। इस दौरान आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण प्रशासनिक शिथिलता दो-ढाई महीने तक बनी रहती है, फलतः विकास कार्य और जन-कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होती हैं। एक साथ चुनाव के चलते सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षाबलों को बार-बार चुनाव ड्यूटी के मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी।

एक साथ चुनाव के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि देश प्रत्येक छह माह बाद चुनावी मूड में आ जाता है, लिहाजा सरकारों को नीतिगत फैसले लेने में तो अड़चनें आती ही हैं, दूसरे नीतियों को कानूनी रूप देने में अतिरिक्त विलंब भी होता है। यह तर्क अपनी जगह जायज है। वैसे भी राजनीतिक दलों की महत्ता तभी है जब वे नीतिगत फैसलों को अधिकतम लोकतांत्रिक बनाने के लिए अपने सुझाव दें व उन्हें विधेयक के प्रारूप का हिस्सा बनाने के लिए नैतिक दबाव बनाएं। ऐसा नहीं है कि एक साथ चुनाव का विचार कोई नया है। 1952 से लेकर 1967 तक चार बार लोकसभा व विधानसभा चुनाव पूरे देश में एक साथ ही हुए हैं। इंदिरा गांधी का केंद्रीय सत्ता पर वर्चस्व कायम होने के बाद राजनीतिक विद्वेश व बेजा हस्तक्षेप के चलते इस व्यवस्था में बदलाव आना शुरू हो गया। इंदिरा गांधी को विपक्ष की जो सरकार पसंद नहीं आती थी, उसे वे कोई न कोई बहाना ढूंढकर अनुच्छेद-356 के तहत राष्ट्रपति से बर्खास्त करा देती थीं। नतीजतन मध्यावधि चुनावों की परिपाटी पड़ती चली गई। इससे राज्यों में अलग-अलग समय पर चुनाव कराने की बाध्यता निर्मित हो गई। अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वस्त होने के बाद पीवी नरसिंह राव ने भी भाजपा शासित कई राज्य सरकारों को गिरा दिया था। वस्तुतः ऐसा अवसर आ गया कि देश में कहीं न कहीं चुनाव की डुगडुगी बजती रहती है। देश का कई करोड़ मतदाता किसी न किसी चुनाव की उलझन में जकड़ा रहता है।

चूंकि संविधान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का उल्लेख तो है, लेकिन दोनों चुनाव एक साथ कराने का हवाला नहीं है। संविधान में इन चुनावों का निश्चित जीवनकाल भी नहीं है। वैसे यह कार्यकाल पांच वर्ष के लिए होता है, लेकिन बीच में सरकार के अल्पमत में आ जाने के कारण या किसी अन्य कारण के चलते सरकार गिर या गिराई जा सकती है। केंद्रीय विधि आयोग ने 2018 में केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया था कि पांच साल के भीतर यदि सरकार के भंग होने की स्थिति बने तो 'रचनात्मक अविश्वास' मत हासिल किया जाए। मसलन, किसी सरकार को लोकसभा या विधानसभा के सदस्य अविश्वास मत से गिरा सकते हैं, तो इसके विकल्प में जिस दल या गठबंधन पर विश्वास हो या जिसे विश्वास मत हासिल हो जाए, उसे बतौर नई सरकार की शपथ दिला दी जाए।' कुछ विपक्षी दल एक साथ चुनाव के पक्ष में शायद इसलिए नहीं हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि ऐसा होने पर जिस किसी दल ने अपने पक्ष में माहौल बना लिया तो केंद्र व ज्यादातर राज्य सरकारें उसी दल की होंगी? ये दल भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सनातन हिंदुत्व की हवा से अधिक भयभीत हैं। पश्चिम बंगाल में एकतरफा जीत ने इनका भय और बढ़ा दिया है। ऐसे में यदि एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो कांग्रेस समेत क्षेत्रीय दलों का भी सूपड़ा साफ होता दिखाई दे सकता है।

बार-बार चुनाव की स्थितियां निर्मित होने के कारण सत्ताधारी राजनीतिक दल को भी यह भय बना रहता है कि उससे कहीं कोई ऐसा नीतिगत फैसला न हो जाए कि दल के समर्थक मतदाता नाराज हो जाएं? लिहाजा सरकारों को लोक-लुभावन फैसले लेने पड़ते हैं। वर्तमान में अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, स्वीडन, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका और फीलिपिंस ऐसे देश हैं, जहां एक साथ चुनाव बिना किसी बाधा के संपन्न होते हैं। गोया, भारत में भी यदि एक साथ चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ होती है तो केंद्र व राज्य सरकारें बिना किसी दबाव के देश व लोक हित में फैसले ले सकेंगी। सरकारों को पूरे पांच साल विकास व सुशासन को सुचारू रूप से लागू करने का अवसर मिलेगा। अतएव दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सांसदों को देश हित में आत्मनिर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि इस विधि से धन की भी बड़ी बचत होगी।

अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (22 मई) पर विशेष

प्रकृति का संकट और जैव विविधता बचाने की वैश्विक चुनौती

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाने का उद्देश्य पृथ्वी पर मौजूद जंतुओं और पौधों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लोगों में जागरूक और समझ को बढ़ाना है। विश्व वन्यजीव दिवस 2026 का थीम "वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना" है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि कैसे समुदाय और स्थानीय स्तर पर किए गए छोटे-छोटे प्रयास मिलकर जैव विविधता के नुकसान को रोकने और पलटने में एक बड़ा वैश्विक बदलाव ला सकते हैं। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी कीट विज्ञानी इ.ओ विल्सन द्वारा 1986 में 'अमेरिकन फोरम ऑन बायोलोजिकल डाइवर्सिटी' में प्रस्तुत रिपोर्ट में किया गया। यह शब्द दो शब्दों अर्थात् 'और का समूह है जो हिन्दी में भी' 'जैव' तथा 'विविधता' द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसका साधारण अर्थ जैव जगत में व्याप्ति विविधता से है।

जैव विविधता से आशय जीवधारियों (पादप जीवों) की विविधिता से है जो दुनिया भर में हर क्षेत्र, देश और महाद्वीप पर होती है। भारत में कुछ जीव जंतुओं की बात करें तो जैव विविधता पर दिसम्बर 2018 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (सीबीडी) में पेश की गई। छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट से पता चला था कि "अंतराष्ट्रीय रेड लिस्ट" की गंभीर रुप से लुप्तप्राय: और संकटग्रस्त श्रेणियों में भारतीय जीव प्रजातियों की सूची वर्षो से बढ़ रही है। विश्व वन्यजीव कोष की लीविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 में खुलासा हुआ है कि दुनिया भर में पिछले 50 वर्षों में वन्य जीवों की आबादी 69 फीसदी कम हुई है। इनमे स्तनधारी, पक्षी, उभयचर, सरीसृप, मछलियां आदि शामिल हैं। हर दो साल में प्रकाशित होने वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक वैसे तो पुरी दुनिया में वन्य जीवों की आबादी तेजी से घट रही है लेकिन 1970 के बाद से लैटिन अमेरिका तथा करेबियाई क्षेत्रों में वन्य जीव आबादी में करीब 49 फीसदी तक की गिरावट आई है जबकि अफ्रीका में 66 फीसदी और एशिया में 55 फीसदी गिरावट हुई है। मछली पकड़ने में 18 गुणा वृद्धि के कारण मछलियों की संख्या में कमी हुई है जबकि ताजा पानी में रहने वाले प्रजातियों में सर्वाधिक 83 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है जो किसी भी प्रजाति की समूह की तुलना में सबसे बड़ी गिरावट है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की रिपोर्ट से साफ है कि धरती पर मौजूद प्रजातियों की तादाद में दस में से सात का आस्तित्व समाप्त हो चूका है। भारत की हालत वैश्विक स्थिति से भिन्न नहीं है। यहां भी 12 फीसदी से अधिक जंगली स्तनधारियों, 3 फीसदी पक्षी प्रजातियों और 19 उभयचरों की प्रजातियों पर गंभीर खतरा है। एक अनुमान के अनुसार करीब तीस करोड़ प्रजातियां हो सकती है जिसमे 14 लाख 35 हजार 662 प्रजातियों की पहचान हुई है। उनमें 7 लाख 51 हजार कीट, 2 लाख 81 हजार जंतु, 68 हजार कवक, 26 हजार शैवाल, 4 हजार 800 जीवाणु तथा एक हजार विषाणु शमिल है। इसके अलावा 343 मछलियां 50 जलथलचारी, 170 सरीसृप, 1355 अकशेरू, 1037 पक्षियों और 497 स्तनपायी की प्रजातियां भी हैं। हर साल परितंत्रों के क्षण के कारण 27 हजार प्रजातियां लुप्त हो रही है। इस लुप्त होती प्रजातियों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। अन्यथा परिणाम भयंकर होंगे। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वनों की कटाई, सभी प्रकार के प्रदूषण, औद्योगीकरण, शहरीकरण जलवायु संकट तथा विभिन्न बिमारियां इनका प्रमुख कारण हैं। डबल्यू डबल्यू एफ के महानिदेशक मार्को लैबर्टनी के अनुसार हम मानव प्रेरित जलवायु संकट व जैव विविधता के नुकसान की दोहरी आपात स्थिति की सामना कर रहे है जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए खतरा साबित हो सकती है।

जैव विविधता प्रत्येक राष्ट्र की विरासत के स्वाभाविक रुप से महत्तवपूर्ण रुप से महत्वपूर्ण पहलू के रुप में और एक उत्पादक, स्थायी संसाधन के रुप मे देखी जानी चाहिए, जिस पर हम सभी अपने वर्तमान और भविष्य के कल्याण के लिए निर्भर है। विकासशील और विकसित दोनों देशों में जैव विविधता की रक्षा के लिए तत्काल कारवाई करने की आवश्यकता है। जैव विविधता पर अनुसंधान की निरंतर आवश्यकता है जो हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, हमारी प्रबन्धन क्षमताओं में सुधार करती है और लोगों के साथ रहने के नए तरीकों के विकास की ओर ले जाती है। कुल मिलाकर, मानव कल्याण के लिए जैव विविधता के कई योगदान अधिक स्पष्ट होते जा रहे हैं। हम अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन, अपने कपड़े और निर्माण सामग्री को 'जैव विविधता' से जोड़ते हैं। यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसे निरंतर प्रबंधित करने और सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि बदले में यह हमारी और ग्रह की रक्षा करें।

प्यास की दहलीज पर भविष्यः क्या पानी के लिए ज़मीन भी हाथ खड़े कर रही है?

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

"पानी केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि सभ्यता की सांस है। जिस दिन यह सांस टूटेगी, विकास के सारे दावे धूल बन जाएंगे।"

हम अक्सर कहते हैं कि मौसम बदल गया है, गर्मियां अब पहले जैसी नहीं रहीं। पारा 45-46 डिग्री के पार पहुंचने लगा है, हवा में तपिश बढ़ गई है और प्रकृति के इस उग्र प्रकोप के सामने धरती का धैर्य जैसे टूटता जा रहा है। वैश्विक स्तर पर सक्रिय हुए एल-नीनो के दंश ने हमारे पूरे मौसम चक्र को बिगाड़ कर रख दिया है, लेकिन इस नाराजगी का सबसे भयावह चेहरा सिर्फ झुलसाती लू नहीं है। असली डर उस खाली बर्तन और हांफते ट्यूबवेल का है, जो एक बूंद पानी के लिए चीख रहे हैं। जल संकट और 'डे ज़ीरो' की आहट अब कोई दूर की आशंका नहीं, बल्कि हमारे दरवाजे पर खड़ी वर्तमान की सबसे कठोर सच्चाई है। हालात इतने विकराल हैं कि जिन शहरों को कभी "वाटर सरप्लस" कहकर सराहा जाता था, आज वहीं टैंकरों की अंतहीन कतारें और पानी के लिए संघर्ष करती पथरीली आंखें दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है मानो सचमुच पानी देने से अब इस ज़मीन ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं।

पाताल भी रीताः जब ज़मीन ने हाथ खड़े कर दिए

मानव ने धरती को एक अंतहीन भंडार समझकर उससे सिर्फ लेना सीखा, लौटाने की जिम्मेदारी हम भूल गए। सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड (CGWB) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत हर वर्ष लगभग 230 से 240 अरब घन मीटर भूजल निकाल रहा है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाले कुल भूजल का लगभग एक-चौथाई (25%) हिस्सा अकेले हमारा देश खपत कर रहा है। परिणाम अब सामने हैं। देश के 54 प्रतिशत से अधिक पारंपरिक जल स्रोत- कुएं, बावड़ियां, तालाब या तो सूख चुके हैं या गंभीर संकट में हैं। कभी 40-50 फीट पर मिलने वाला पानी अब 600 से 800 फीट नीचे भी मुश्किल से मिल रहा है। बोरवेल की अंधी दौड़ ने धरती के सीने को छलनी कर दिया, तो वहीं शहरों में फैले सीमेंट और कंक्रीट के जाल ने मिट्टी की वह सांसें बंद कर दी हैं, जिससे बारिश का पानी रिसकर भूजल को रीचार्ज करता था।

इन्दौर से देश तकः 'डे ज़ीरो' की दस्तक

नीति आयोग की "कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स" रिपोर्ट ने वर्षों पहले जिस "डे ज़ीरो" की चेतावनी दी थी, वह अब हकीकत में बदल रही है। देश के 21 बड़े शहर इस समय भूजल संकट की कगार पर खड़े हैं। इन्दौर और मालवा क्षेत्र, जो कभी अपने बेहतरीन पारंपरिक जल प्रबंधन के लिए मिसाल माने जाते थे, आज इस भीषण चुनौती से सीधे जूझ रहे हैं। मालवा की भौगोलिक संरचना 'बेसाल्ट चट्टानों' वाली है, जो भूजल संचयन के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। अत्यधिक दोहन के कारण मई की इस धूप में कई इलाकों का वाटर लेवल 200 से 300 फीट तक नीचे खिसक गया है। बढ़ते तापमान के कारण नर्मदा का बैकवॉटर और बड़े जलाशय भी तेजी से वाष्पीकरण का शिकार होकर पीछे हट रहे हैं, जिससे सप्लाई व्यवस्था पर भारी दबाव है। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी में केवल 2.5 प्रतिशत ही मीठा और उपयोग योग्य है, जिसका बड़ा हिस्सा ग्लेशियरों में कैद है। जो पानी हमारी नदियों और भूमिगत स्रोतों में बचा भी है, उसका 70 प्रतिशत हिस्सा औद्योगिक कचरे, रसायनों और सीवेज के कारण प्रदूषित हो चुका है। यानी संकट केवल पानी की कमी का नहीं, बल्कि साफ़ पानी की भारी किल्लत का है।

एल-नीनो का दंश और बदलता मौसम चक्र

इस जल संकट के पीछे प्रकृति की नाराजगी और इंसानी गलतियों का एक खतरनाक घालमेल है। हाल के वर्षों में आए 'एल-नीनो' के प्रभाव ने देश भर में वर्षा के पैटर्न को पूरी तरह बिगाड़ दिया। कमजोर मानसून, सर्दियों में असामान्य रूप से कम ठंड और असमय बढ़ती गर्मी ने ज़मीन की बची-कुची नमी को भी सोख लिया है। कंक्रीट के जंगलों के कारण जब बारिश का पानी ज़मीन में समाने के बजाय तेजी से बहकर नालों में निकल जाता है, तो भूजल रीचार्ज नहीं हो पाता। यही वजह है कि पारा चढ़ते ही हमारे नलकूप हांफने लगते हैं, क्योंकि नीचे प्रकृति का 'वाटर बैंक' खाली हो चुका होता है।

व्यर्थ बहता अमृत और सिकुड़ती नदियां

एक ओर लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी लापरवाही स्थिति को और विकराल बना रही है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़े बताते हैं कि भारत में शहरी सप्लाई का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा पाइपलाइनों के लीकेज, अव्यवस्थित वितरण और अनियंत्रित बर्बादी में नष्ट हो जाता है। गाड़ियों को घंटों पाइप से धोना, सड़कों पर अनावश्यक छिड़काव करना और घरों में खुले नलों से पानी बहने देना- ये केवल खराब आदतें नहीं हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के हिस्से का जीवन छीनने जैसा अपराध है। जब तापमान बढ़ता है, तो जलाशयों से पानी उड़ने की रफ्तार 15 से 20 प्रतिशत बढ़ जाती है। नदियां सिकुड़ रही हैं, बांध खाली हो रहे हैं और हमारी पूरी निर्भरता उस पाताल पर है जिसे हम पहले ही सुखा चुके हैं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)